Indian Council of Agricultural Research have been requested to intensify their research programme in respect of sugarcane.

Fertiliser shortage

2601. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the fertiliser industry is able to meet the needs of the consumers in the country;

(b) what is the estimated shortge, if any;

(c) what steps are being taken to meet the shortage; and

(d) what steps are being taken to increase the production of fertilizers in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION (SHRI (YOGENDRA MAKWANA): (a) No, Sir.

(b) and (c) The gap between the requirements and indigenous availability is adequately covered through imports.

(d) A major programme has been taken on hand for augmentation of fertilizer production capacity in the public, private and cooperative sectors. With the implementation of this programme, the installed capacity for production of fertilizers would increase from the present level of 5.9 million Tonnes of Nitrogen and 1.57 million Tonnes of P.O. to about 9.5 Milllion Tonnes of Nitrogen and 2.9 Million Tonnes of P|O s by end of Seventh Plan (1989-90).

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड आवासीय क्षेत्र में पार्कों का विकास

2602. डा० गोविन्द दास रिछारिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल के अभाव में दिल्ली विकास प्राधिकरण की लारेंस रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत सारे पार्क नष्ट हो रहे है ;

(ख) क्या यहां के अधिकांश "ट्यूबवैल" वर्षों से खराब पड़े हैं तथा मध्य आय वर्ग की सी-2 कालोनी में पार्कों की पाइप लाइनें भी अवरुद्ध पड़ी हैं;

(ग) क्या पार्कों की दीवारें, ग्रिल व बच्चों के झूले भी टूटे-फूटे पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन पार्कों की दशा को सुधारने के लिए तथा जल की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां, वहां पानी की कमी है।

(ख) तीन नलकूपों में से दो सही काम कर रहे हैं उन में से एक सूख गया है ।

(ग) इन मदों की मरम्मत की जरूरत है ।

(घ) पार्कों के लिए जलपूर्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नलकूप लगाने का प्रस्ताव है । पार्कों में दीवारों, ग्रिलों, झूलों, की मरम्मत/अनुरक्षण के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

2603. [*Transferred to to the 19th December,* 1985].

कम क्षमता वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों में बदला जाना

2604. डा० गोविन्द दास रिछारिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदर्शन के "लो पावर ट्रांसमीटर" रिले केन्द्रों में से कुछ को "हाई पावर ट्रांसमीटर" रिले केन्द्रों में बदलने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कहां-कहां के रिले केन्द्रों को "हाई पावर ट्रांसमीटर" रिले केन्द्रों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार झांसी स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र का बिस्तार करने का भी विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक होगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) उन स्थानों जहां पर अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति (10/1 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं, का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1985–86 :
जम्मू और विशाखापत्नम ।

1986–87 :
अगरतला, डिब्रूगढ़, तुरा, कोहिमा, इम्फाल तथा शिलांग।

(ग) झांसी के अन्य शक्ति वाले दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है ।

(घ) दूरदर्शन सेवा का विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है । इस प्रकार झांसी के आस-पास कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना संसाधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

Projects aided by Council for Advancement of Rural Technology

2605. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the names of projects sanctioned and aided by the Council for Advancement of Rural Technology (CART) till the end of the year 1985; and

(b) what is the contribution in research, development and dissemination of rural technology by the projects aided and funded by the CART?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) Names of the Projects sanctioned till 10th December, 1985 are given in the Annexure. [*See* Appendix CXXXVI, Annexure No. 49].

(b) As would be seen from the list of projects, most of these are demonstration or pilot projects for the dissemination of different rural technologies which have been already developed. A few also have a research component. As these projects have been taken up for implementation only in the last one and half years, it is still too early to evaluate their contribution. These ongoing projects are being regularly monitored.

Economy Drive in the Ministry of Information and Broadcasting

2606. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) Whether his Ministry has launched economy drive in various media divisions;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what will be the likely saving as a result of the drive?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) to (c) A quick review of the non-plan budget provisions of the Ministry of Information and Broadcasting and Media Units was recently carried out with a view to identifying areas where economy in expenditure can be achieved without affecting their efficiency or essential activities. A saving of nearly Rs. 6.28 crores was located in the Sanctioned Budget Grant of Rs. 238.07 crores (Non-plan) for 1985-86 of the Ministry of Information and Broadcasting and its attached and subordinate offices.